भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी

प्रेस विज्ञप्ति

20 नवंबर, 2014

पेंडारी (बिलासपुर)–महिलाओं की नसबंदी हत्याओं के विरोध में

हमारी पार्टी पेंडारी–बिलासपुर के शर्मनाक व गैर–जिम्मेदाराना नसबंदी कांड के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को पत्यक्ष जिम्मेदार ठहराती है। गरीब व आदिवासी जनता के स्वास्थ्य के प्रति उसकी साजिशाना व आपराधिक लापारवाही की घोर निंदा करती है। पेंडारी सहित अन्य नसबंदी शिविरों में मारी गयी एवं गंभीर रूप से अस्वस्थ महिलाओं के शोक–संतप्त परिवारजनों के प्रति सांत्वना व सहानुभूति प्रकट करती है। स्वास्थ्य मंत्री व मुख्यमंत्री के द्वारा राज्य की जनता से क्षमा याचना करने और उनके इस्तीफे की मांग को लेकर सड़क पर उतरने जनवादी–प्रगतिशील ताकतों, मानवधिकार कार्यकर्ताओं, मजदूर–किसनों, महिलाओं, मीडियाकर्मियों, डॉक्टरों व स्वास्थ्यकर्मियों का आह्वान करती है।

दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी इंडियन मेडिकल एसोसियेशन की छत्तीसगढ़ राज्य इकाई से अपील करती है कि वह पेंडारी–बिलासपुर महिलाओं की नसबंदी हत्याओं के संदर्भ में जनविरोधी रमन सरकार को अपने आंदोलन का निशाना बनायें और मारी गयी महिलाओं के शोक संतप्त परिवारजनों एवं मौत से जूझ रही नसबंदी की शिकार महिलाओं के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद करें।

आम जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रति सरकार की गैर–जवाबदेही न सिर्फ नसबंदी शिविरों बल्कि विगत में आंखों के इलाज से संबंधित शिविरों में भी सामने आयी थी। सरकारी स्वास्थ्य शिविरों में इलाज के लिए जाना महंगा साबित हो रहा है। अंधत्व से छुटकारा पाने की आस में कई मरीजों ने हमेशा के लिए अपनी आंखें खो दी थी। सरकारें स्वयं को जन कल्याणकारी होने की डींगें हांकती हैं जबकि सच्चाई यह है कि गरीब जनता के स्वास्थ्य के प्रति वे घोर व षड्यंत्रपूर्ण लापारवाही इसलिए बरतती हैं ताकि लोग सरकारी अस्पतालों, शिविरों से मुंह मोड़ ले जिससे एक ओर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी से छुटकारा मिल जाएं एवं दूसरी ओर निजी व कॉरपोरेट अस्पतालों की चांदी हो जाएं। प्रतिबंधित व नकली दवाइयां बनाने वाले पूंजीपतियों व बहुराष्ट्रीय कंपनियों को संरक्षण देने वाली सरकार गरीब जनता को मौत के मुंह में ढ़केल रही है। सरकारों की जनविरोधी एवं सामंती, पूंजीपति व बहुराष्ट्रीय कंपनी परस्त नीतियों के चलते देश की जनता गरीबी, भूखमरी, बीमारी, अशिक्षा, आवासहीनता जैसी मूलभूत समस्याओं से जूझ रही है। जबकि सरकारें यह कहते नहीं थकती हैं कि गरीबों की बढ़ती आबादी ही इन तमाम समस्याओं की जड़ है। इसीलिए नसबंदी को इन तमाम समस्याओं के सामाधान के रूप में प्रचार किया जाता है और गैर–जिम्मेदाराना ढ़ंग से नसबंदी शिविरों का आयोजन किया जाता है। आदिवासी एवं गैर–आदिवासी गरीब जनता को अनुचित तरीके से नसबंदी के लिए प्रोत्साहित किया जाता है या जबरिया नसबंदी कराया जाता है। इससे आदिवासी इलाकों की प्राचीनतम आदिवासी जनजातियों के लुप्त होने का खतरा भी उत्पन्न हो गया है।

नसबंदी के बारे में आवश्यक शिक्षा संयम के साथ लगातार दिया जाना चाहिए ताकि लोग स्वयं ही इस संबंध में उचित निर्णय ले सके। इस संदर्भ में हमें इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि जितनी आबादी बढ़ती है, उसके दोगुने हाथ काम करने तैयार होते हैं। हर हाथ को काम देने से खाने की कमी नहीं होगी। हमारे देश में जल, जंगल, जमीन व संसाधनों की कमी नहीं है लेकिन संसाधनों का इस्तेमाल समस्त जनता के हित में न होकर देशी–विदेशी पूंजीपतियों के हित में हो रहा है। इस विडंबना को दूर करने से ही जनता की खुशहाली संभव है। आत्मनिर्भरता, असली विकास व असली आजादी के लिए शोषक–शासक वर्गों के खिलाफ आन्दोलन के सिवाय कोई चारा नहीं है।

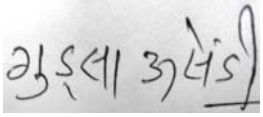

(गुड्सा उसेण्डी)

प्रवक्ता,

दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी,

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)